ریفنڈ کے پیسے واپس لینے کے لئے دو-تین مہینے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اتنے دنوں تک یہ انیر لائنس اس پیسے کو اپنے استعمال میں لاتی ہیں۔ فی الحال پرانیویٹ انیر لائنس کو منمانے کینسلیشن چارج وصول کرنے سے روکنے کے لئے کوئی میکینزم نہیں ہے اور بقایا پیسے واپس کرنے کے لئے بھی کوئی مدّت مقرّر نہیں کی گئی ہے، جس کا ناجائز فائدہ پرائیویٹ انیر لائنس اٹھا رہی ہیں۔ اس لئے اس سدن کے مادھیم سے میں سول ایوئیشن منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ پرائیویٹ انیر لائنس بھی انیر انڈیا کے برابر کینسلیشن چارج وصول کریں اور بقایا رقم کو جلد سے جلد مسافروں کو واپس کر دیں۔

(ختم شد)

Demand to review the decision of allowing foreign direct investment into retail sector of the country

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सचिवों की समिति द्वारा देश में बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 फीसदी की सिफारिश से खुदरा बाजार में लगे देश के कोने-कोने में किराना व छोटे-मझोले व्यवसाय करने वाले व्यापारियों तथा कामगारों के हित इस कदम से चरमराने वाले हैं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कुचक्र में फंसकर दशकों पुरानी भारतीय व्यापारिक व्यवस्था इस अनुमति से दम तोड़ देगी।

एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी और थोक बाजार में 100 फीसदी की अनुमति एफडीआई को पहले से ही मिली हुई है। परिणामस्वरूप देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हिस्सेदारी बाजार पर 15 फीसदी के आसपास है। यदि सचिवों की समिति की संस्तुति को सरकार मान लेती है तो देश के बाजारों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हिस्सेदारी 15 से बढ़कर 100 फीसदी हो जाएगी, जिससे देश का व्यवसायी पूरी तरह से प्रभावित होगा और पिछड़ जाएगा।

मेरा आग्रह है कि सचिवों की समिति द्वारा एफडीआई की अनुमति देने के सुझाव पर पुनः विचार हो और देश के व्यापारियों के हितों से जुड़े हर पहलू को बड़ी सावधानी से जांचा-परखा जाए। इसके अलावा यह सुनिश्चित हो कि छोटे व्यापारियों को ऐसी किसी भी अनुमति से कोई नुकसान न हो, नहीं तो आगे चलकर परिणाम घातक होंगे और फिर संभलने का वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं तब तक चरमरा चुकी होंगी। धन्यवाद।

Demand to restore the availability of coal and power to the State of Madhya Pradesh

श्री कमान सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को मिलने वाले बिजली के कोटे को बार - बार कम किया जा रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है।

†Transliteration in Urdu Script.